Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

अप्रैल

(संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं का किया शिलान्यास 3
- उत्तराखंड में लगेंगे 25 हज़ार MSME उद्योग 4
- प्रदेश में वाइब्रेंट गाँवों की संख्या में होगा इजाफा 5
- उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी-2023 का खाका पेश 6
- स्मार्ट स्प्रिचुअल हिल टाउन का रूप लेगा बदरीनाथ 6
- लोक भाषाओं के लेखकों को हर साल मिलेगा 'उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान' 7
- मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम और 40 टू नेट मशीनों का लोकार्पण 8
- अब पूरे देश में बिकेगी चमोली की जड़ी-बूटियाँ, आयुष मंत्रालय ने 48 काश्तकारों को किया पंजीकृत 8
- उत्तराखंड में वनाग्नि 9
- उत्तराखंड में स्टेट हाईवे पर बने 288 पुल होंगे अपग्रेड 9
- प्रदेश में वर्ष 2021-22 के ज़िलावार प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े हुए जारी 10
- उत्तराखंड में 'ए-हेल्प'कार्यक्रम की शुरुआत 11
- मुख्यमंत्री ने गंगा समग्र 'अविरल गंगा निर्मल गंगा' कार्यक्रम का शुभारंभ किया 12
- प्रदेश में पाँच ज़िलों में बनेंगे सगंध फसलों के सेटेलाइट केंद्र 12
- उत्तराखंड के 603 प्राथमिक, 76 उच्च प्राथमिक बनेंगे क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय ++ 13
- गढ़वाल और कुमाऊँ के छह इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस 13
- उत्तराखंड फूड लैब को मिला नया हॉलमार्क 14
- गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क माफ 14
- उत्तराखंड का माणा अब देश का अंतिम नहीं पहला गाँव 15
- आयुष्मान कार्ड पर अब सेना व पैरामिलिट्री अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज 16
- जौलीग्रांट में एसडीआरएफ के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण 16
- आयोग के प्रस्ताव को शासन ने लौटाया, अब उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही होगी PCS परीक्षा 17
- उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन 18
- एयर एंबुलेंस सेवा के लिये एम्स और पिनाकल कंपनी में हुआ एमओयू 18

दृष्टि The Vision

नोट :

उत्तराखंड

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं का किया शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देहरादून में आयोजित समारोह में जोशीमठ से वर्चुअल माध्यम के जरिए उत्तराखंड के देहरादून में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और रुद्रप्रयाग, नैनीताल व श्रीनगर में 50 बिस्तरों वाले तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन'(पीएम-एबीएचआईएम) के तहत चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है तथा वैश्विक कोविड महामारी के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की चिकित्सा इकाइयों को मज़बूत करने के उद्देश्य से ईसीआरपी-द्वितीय (आपात्कालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज-II) के तहत महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।
- उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम करने के क्रम में पीएम- एबीएचआईएम योजना के तहत 7 और ईसीआरपी-II के तहत 7 यानी कुल 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का निर्माण किया जा रहा है।
- इन पहलों के माध्यम से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपात्कालीन देखभाल के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।
- रुद्रप्रयाग व नैनीताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण ईसीआरपी- II पैकेज के तहत किया जाएगा। वहीं, श्रीनगर में इसका निर्माण पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत किया जाएगा।
- भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के आपसी समन्वय से स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम जनता की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये श्रीनगर के पौड़ी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के हल्द्वानी में 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिये कुल 71.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- इनमें से हर एक गंभीर देखभाल ब्लॉक के निर्माण के लिये 23.75 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन गंभीर देखभाल ब्लॉकों में आईसीयू बेड, एचडीयू बेड, आइसोलेशन वार्ड बेड, आइसोलेशन रूम, इमरजेंसी बेड, ऑपरेशन थिएटर, लेबर डिलीवरी रूम, संयुक्त देखभाल प्रयोगशाला और डायलिसिस रूम जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- राज्य में चिकित्सा अवसंरचना को उन्नत और सुदृढ़ करने के लिये 120 करोड़ रुपए की धनराशि से दून मेडिकल कॉलेज में 500 बिस्तरों की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इस पहल से सुदूर क्षेत्रों से आने वाले रोगियों को राज्य की राजधानी में बेहतर उपचार की सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी।
- इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र हुई प्रगति को रेखांकित करते हुए बताया कि 80,000 से अधिक लोगों के 'ई-रक्तकोष रक्तदान पोर्टल'पर पंजीकृत होने के साथ देश में उत्तराखंड के लोगों ने सबसे अधिक रक्तदान किया है।
- राज्य के लोगों को 50 लाख से अधिक एबीएचए कार्ड जारी किये गए हैं और उनमें से 7 लाख से अधिक लोगों ने इस नि:शुल्क उपचार सुविधा का लाभ उठाया है।
- उत्तराखंड टीबी के खिलाफ लड़ाई में नि-क्षय मित्र पहल के तहत 100 फीसदी टीबी रोगियों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

The Vision

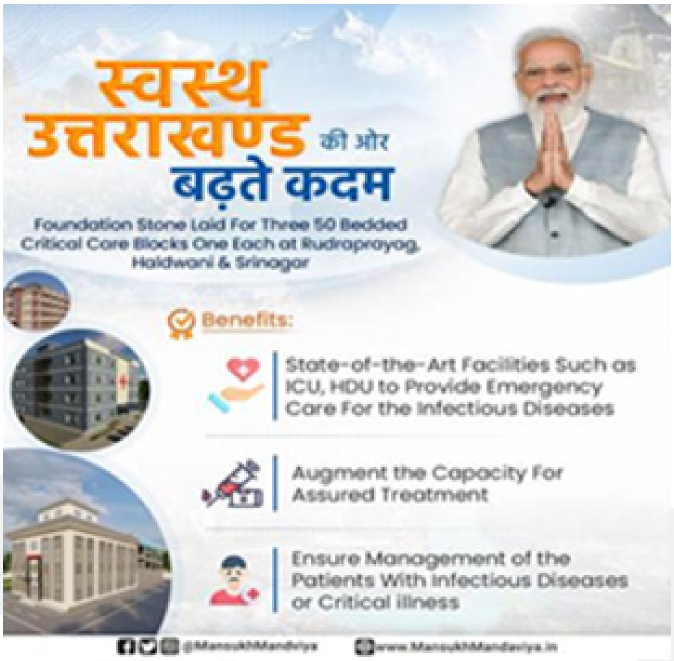
स्वस्थ उत्तराखण्ड की ओर बढ़ते कदम
Foundation Stone Laid For Three 50 Bedded Critical Care Blocks One Each at Rudraprayag, Haldwani & Srinagar
Benefits:
State-of-the-Art Facilities Such as ICU, HDU to Provide Emergency Care For the Infectious Diseases
Augment the Capacity For Assured Treatment
Ensure Management of the Patients With Infectious Diseases or Critical Illness
@MansukhMandviya
www.MansukhMandaviya.in

मुख्य सेवक सदन
"स्वस्थ उत्तराखण्ड की ओर बढ़ते कदम"

उत्तराखंड में लगेंगे 25 हज़ार MSME उद्योग

चर्चा में क्यों ?

2 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोज़गार के नए अवसर सृजित करने के लिये राज्य सरकार ने पाँच साल का रोडमैप तैयार किया है, जिसके अंतर्गत 25 हज़ार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- सशक्त उत्तराखंड के लिये अमेरिका की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल ने राज्य में औद्योगिक विकास का रोडमैप बनाया है। योजना के तहत प्रदेश में 7500 करोड़ का निवेश होगा। इससे एक लाख लोगों को रोज़गार देने का लक्ष्य रखा गया है।

- निवेश को बढ़ावा देने लिये ईज आफ डूईंग बिजनेस, ज़िला स्तर पर निवेश के लिये अवस्थापना विकास, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहयोग और निवेशकों को प्रोत्साहन देने पर सरकार का फोकस रहेगा।
- मैकेंजी ग्लोबल की ओर से निवेश को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन के तौर पर सब्सिडी की सिफारिश की गई है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले नए सूक्ष्म उद्योगों को 75 प्रतिशत (अधिकतम 75 लाख), लघु उद्योगों को 40 प्रतिशत (अधिकतम चार करोड़), मध्यम उद्योगों को 20 प्रतिशत (अधिकतम 10 करोड़) तक सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है।
- राज्य के ऊधमसिंह नगर ज़िले के प्रयाग फार्म के पास एक हज़ार एकड़ ज़मीन पर अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है, जो पंतनगर और रुद्रपुर से काफी नज़दीक है। यहाँ बड़े उद्योग लगाने के लिये ज़मीन उपलब्ध होगी।

प्रदेश में वाइब्रेंट गाँवों की संख्या में होगा इजाफा

चर्चा में क्यों ?

1 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में उत्तराखंड के और नए सीमांत गाँवों को शामिल करेगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि केंद्र सरकार ने सीमांत गाँव नीति, माणा, मलारी और गुंजी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया है। इन गाँवों के विकास के लिये केंद्र सरकार सहयोग करेगी।
- मुख्यमंत्री सीमांत गाँव विकास योजना के तहत भी सीमांत गाँवों में पर्यटन और आर्थिकी गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा को प्रथम गाँव की संज्ञा दी है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले पर्यटक सीमांत गाँव तक जाएं और अपने यात्रा खर्च का पाँच फीसदी इन गाँवों के स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें।
- सीमांत गाँवों को उनकी विशिष्टता के अनुरूप विकसित किया जाए और उनका प्रचार-प्रसार हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहाँ पहुँचे। इससे वहाँ के स्थानीय लोगों की आर्थिकी में सुधार स्थिति होगा और पलायन की समस्या भी कम होगी।

उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी-2023 का खाका पेश

चर्चा में क्यों?

3 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि अमेरिकी संस्था मैकेंजी ग्लोबल ने राज्य में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिये उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी-2023 का खाका पेश किया है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी-2023 के आने से वर्ष 2030 तक राज्य में ड्रोन उत्पादन और सेवाओं से 5000 युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इस क्षेत्र में एक हज़ार करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी-2023 के तहत इस क्षेत्र में ड्रोन निर्माण में 500 करोड़ रुपए और सर्विसेज में 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
- ड्रोन के प्रोत्साहन के लिये राज्य में आईटीडीए के अधीन स्टेट ड्रोन कॉर्डिनेशन सेल (एसडीसीसी) गठित की जाएगी। वहीं, आईटीआई कालसी और आईटीआई काशीपुर को निजी सहभागिता से ड्रोन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर चुना गया है। यहाँ डीजीसीए ने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (आरपीटीओ) बनाने की अनुमति दे दी है।
- मैकेंजी ग्लोबल के इस प्रस्ताव के तहत निजी संस्थानों को ड्रोन संबंधी कोर्स और प्रशिक्षण कोर्स चलाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी कॉलेजों और नैक से प्रमाणित निजी विश्वविद्यालयों में ड्रोन स्कूल स्थापित किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, आईटीडीए ने ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस पर जनता व हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। आईटीडीए द्वारा इस पॉलिसी पर जनसुझाव लेने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

स्मार्ट स्प्रिचुअल हिल टाउन का रूप लेगा बदरीनाथ

चर्चा में क्यों?

4 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सपताल महाराज ने बताया कि राज्य के बदरीनाथ धाम को स्मार्ट स्प्रिचुअल हिल टाउन (आध्यात्मिक पर्वतीय शहर) के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- बदरीनाथ धाम को स्मार्ट स्प्रिचुअल हिल टाउन (आध्यात्मिक पर्वतीय शहर) के रूप में विकसित करने के लिये पहले चरण में 425 करोड़ रुपए की लागत से बदरीनाथ मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया है।
- विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य से केदारपुरी भव्य व दिव्य स्वरूप में विकसित हुई है। 21 फरवरी से अब तक चारधाम यात्रा में केदारनाथ के लिये 3,49,944, बदरीनाथ के लिये 2,91,537, यमुनोत्री के लिये 1,61,149 और गंगोत्री धाम के लिये 1,66,310 यात्री पंजीकरण करा चुके हैं।
- पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। चार धाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर काम जोरों पर चल रहा है। गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तथा सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे को तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य सरकार ने खरसाली से यमुनोत्री तक 166 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि से बनने वाले रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है।
- उल्लेखनीय है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने शाक्त, शैव, वैष्णव, गोलज्यू, गुरुद्वारा, हनुमान, नाग देवता, स्वामी विवेकानंद, महासू देवता, नरसिंह देवता, और नवग्रह देवता सर्किट का निर्माण किया है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु इन सर्किट के दर्शन कर सकते हैं।

लोक भाषाओं के लेखकों को हर साल मिलेगा 'उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान'

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड भाषा संस्थान की बैठक में घोषणा की कि इस साल राज्य सरकार की ओर से लोक भाषाओं व लोक साहित्य में कुमाऊँनी, गढ़वाली, राज्य की बोलियों व उपबोलियों, हिन्दी, पंजाबी, उर्दू में महाकाव्य, खंडकाव्य रचना, काव्य रचना और साहित्य व अन्य गद्य विधाओं के लिये 'उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान' दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि सचिवालय में वर्ष 2014 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में संस्थान की प्रबंध कार्यकारिणी सभा की बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि लोक भाषाएँ व बोलियाँ राज्य की पहचान व गौरव हैं तथा आगामी मई में भव्य समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि धन अभाव के कारण अपनी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करा पाने वाले राज्य के रचनाकारों को भाषा संस्थान की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में आंशिक अनुदान दिया जाएगा।
- यह भाषा संस्थान की एक बहुआयामी योजना होगी, जिसमें शोध पत्रों का वाचन, भाषा संबंधी विचार विनिमय, साहित्यिक शोभा यात्रा, लोक भाषा सम्मेलन आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- उन्होंने राज्य के प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजन करने के तथा प्रत्येक जनपद के एक प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल व ई-पुस्तकालय स्थापित करने के भी निर्देश दिये।
- बैठक के दौरान राज्य में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर पुस्तक मेले में साहित्यिक संगोष्ठियों के आयोजन की भी स्वीकृति दी गई।
- बैठक में उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से साहित्यिक व शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही लोक भाषाओं

के मानकीकरण के लिये कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की स्वीकृति दी गई।

- राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में गढ़वाली, कुमाऊँनी व जौनसारी बोलियों को बोलने वाले व लिखने वाले अलग-अलग हैं, जिनके लेखन में शब्दों का विभेद है। गढ़वाली एवं कुमाऊँनी बोली भाषा वर्तनी के मानकीकरण की आवश्यकता है। संस्थान की ओर से उत्तराखंड में जनपद व राज्य स्तरीय भाषायी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम और 40 ट्रू नेट मशीनों का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड सचिवालय में स्थित विश्वकर्मा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 हेल्थ एटीएम और 40 ट्रू नेट मशीनों का लोकार्पण किया। राज्य सचिवालय में प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- हेल्थ एटीएम के जरिये एक बूंद खून से 30 सेकेंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधी 72 तरह की जाँच की जाएगी।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ एटीएम स्थापित होने से जाँच के लिये अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिये यात्रा मार्गों पर हेल्थ एटीएम स्थापित किये जाएंगे।
- कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यश बैंक, जेके टायर ने हेल्थ एटीएम और ट्रू नेट मशीनें दी हैं।
- यश बैंक के माध्यम से सचिवालय, विधानसभा के साथ टनकपुर चिकित्सालय में एक-एक हेल्थ एटीएम स्थापित किये गए हैं। जेके टायर कंपनी ने पुलिस लाइन, जेएलएन ज़िला चिकित्सालय नैनीताल, संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जसपुर, उप ज़िला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा में एक-एक हेल्थ एटीएम स्थापित किये है।
- मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग और कंपनियों के बीच एमओयू किया गया।
- इंडियन ऑयल कॉरपोरशन लिमिटेड के सौजन्य से सीएसआर के तहत 40 ट्रू नेट मशीनों को ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाएगा। इससे टीबी के साथ कोविड की जांच भी हो सकेगी।
- हेल्थ एटीएम के जरिये स्वयं भी अपनी जाँच कर सकते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी एंड डीएलसी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक ऐसिड, कॉलेस्ट्राल, एचबीए1-सी, ब्लड ग्रुप, लिपिड प्रोफाइल, ट्राईगिलसाइड, लाइकोप्रोटीन, प्रेगनेंसी टेस्ट, किडनी टेस्ट, हैपेटाइटिस, चिगनगुनिया, मलेरिया, बीएमसी, बीएमआई, शरीर का तापमान, ऑक्सीजन स्तर, शरीर में पानी की मात्रा, ईसीजी समेत 72 टेस्ट किये जा सकते हैं। इन हेल्थ एटीएम पर यह जाँच निशुल्क होगी।

अब पूरे देश में बिकेगी चमोली की जड़ी-बूटियाँ, आयुष मंत्रालय ने 48 काश्तकारों को किया पंजीकृत

चर्चा में क्यों?

9 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चमोली जनपद में जड़ी-बूटी की खेती कर रहे 48 काश्तकारों को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने पंजीकृत कर लिया है। अब ये काश्तकार देश के किसी भी कोने में जड़ी-बूटियाँ बेच सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- विदित हे कि चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों के गाँवों के काश्तकार बड़े पैमाने पर कुटकी व अन्य जड़ी-बूटियों की खेती कर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं।
- बीते वर्ष चमोली जनपद के काश्तकारों ने करीब दो करोड़ रुपये की कुटकी बेची। देवाल ब्लॉक के घेस और वाण गाँव में करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर काश्तकार कुटकी का उत्पादन कर रहे हैं। प्रत्येक तीन साल में तैयार होने वाली कुटकी की कीमत 1200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- श्रीनगर गढ़वाल की ह्यूमन हिलर्स कंपनी किसानों से कुटकी खरीदती है। गढ़वाल विश्वविद्यालय कुटकी की खेती में सहयोग देता है।
- गौरतलब है कि हिमालय क्षेत्र के गाँवों में जड़ी-बूटी कृषिकरण पर भारत सरकार का आयुष मंत्रालय एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा है। आयुष

मंत्रालय कुटकी की खेती के लिये 70 फीसदी की सब्सिडी पर ऋण देता है। इसी क्रम में मंत्रालय अब कुटकी की खेती, काश्तकारों की समस्याओं, अधिक से अधिक काश्तकारों को जड़ी-बूटी की खेती से जोड़ने के लिये डॉक्यूमेंट्री बना रहा है।

- उल्लेखनीय है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में 2700 से 4500 मीटर की ऊँचाई पर पैदा होने वाली जड़ी-बूटी कुटकी खून साफ करना, ताकत, ज्वार और शुगर की दवा के रूप में काम आती है। कुटकी पीलिया, हेपिटाइटिस, एलर्जी, अस्थमा और त्वचा की बीमारियों के उपचार में भी काम आती है। इसके अलावा गठिया, रक्त विकार, हिचकी और उल्टी की दवाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है।

उत्तराखंड में वनाग्नि

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में इस सीजन में वनाग्नि की 120 घटनाओं में अब तक 183.35 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचा है।

प्रमुख बिंदु

- मिली जानकारी के अनुसार गढ़वाल में अब तक 62 घटनाओं में 91.53 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जबकि कुमाऊँ में 44 घटनाओं में 55.30 हेक्टेयर और वन्यजीव विहारों में 14 घटनाओं में 36.52 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
- मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि मौसम के बदलते रुख के साथ तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। इससे वनों में आग की घटनाएँ बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।
- प्रदेश में अनियमित वर्षा के पैटर्न के चलते बीते कुछ सालों से शीतकाल में भी आग की घटनाएँ बढ़ गई हैं। हालाँकि, ग्रीष्मकाल में ही जंगलों को आग का खतरा सर्वाधिक रहता है। मार्च से जून तक का समय आग के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। खासकर कम वर्षा होने और वातावरण शुष्क होने के कारण जंगल की आग तेजी से फैलती है।

उत्तराखंड में स्टेट हाईवे पर बने 288 पुल होंगे अपग्रेड

चर्चा में क्यों ?

- 10 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में स्टेट हाईवे पर बने 288 सिंगल लेन पुलों को अपग्रेड करते हुए

डेढ़ लेन में बदला जाएगा। इस संबंध में राज्य लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की ओर से आदेश जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि बीते वर्ष शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश भर में 3262 में से 2518 पुलों की सेफ्टी ऑडिट कराया था। राज्य के पाँच ज़ोन में कराए गए सेफ्टी ऑडिट में 36 पुल आवागमन के लिये असुरक्षित पाए गए थे।
- प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि प्रदेश में सामरिक दृष्टि और यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलों की भार क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- राज्य के 288 सिंगल लेन बी लोडिंग श्रेणी के इन पुलों को ए श्रेणी में अपग्रेड करते हुए इनकी भार क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। इन पर कुल 19.23 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में 182 पुलों के लिये 12.73 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिये गए हैं।
- इनमें उत्तरकाशी ज़िले में 12 पुलों, चमोली ज़िले में 19 पुलों, रुद्रप्रयाग में 10 पुलों, देहरादून में 25 पुलों, पौड़ी में तीन पुलों, पिथौरागढ़ में चार पुलों, बागेश्वर में दो पुलों, अल्मोड़ा में सात पुलों, चंपावत में तीन पुलों, नैनीताल में 11 पुलों और ऊधमसिंहनगर में आठ पुलों के लिये राशि जारी किये गए हैं।
- कुल स्वीकृत पुलों की संख्या -

उत्तरकाशी	13
चमोली	38
रुद्रप्रयाग	12
देहरादून	25
पौड़ी	06
पिथौरागढ़	09
बागेश्वर	03
अल्मोड़ा	47
चंपावत	10
नैनीताल	11
ऊधमसिंहनगर	08
कुल	182

प्रदेश में वर्ष 2021-22 के ज़िलावार प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े हुए जारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने वर्ष 2021-22 के ज़िलावार प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े जारी किये हैं। इससे पूर्व गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की थी।

प्रमुख बिंदु

- जारी आँकड़ों के अनुसार औद्योगिक नगरी बन चुके हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून ज़िले प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे हैं।

- हरिद्वार राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला ज़िला बन चुका है, वहीं गढ़वाल मंडल का रुद्रप्रयाग ज़िले की प्रति व्यक्ति आय राज्य के बाकी 12 ज़िलों में सबसे कम है।
- रिपोर्ट में प्रचलित भाव पर वर्ष 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपए वार्षिक होने का अनुमान लगाया गया। वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति 2,05,840 रुपए आँकी गई थी, लेकिन ज़िलावार प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े तैयार नहीं हो पाए थे। प्रचलित भाव पर देश की प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 है।
- पिछले एक दशक में पहाड़ की तुलना में मैदानी ज़िलों में समृद्धि का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हरिद्वार जिले की सबसे अधिक 362688 रुपए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है। दूसरे स्थान पर 269070 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ ऊधमसिंह नगर ज़िला है और तीसरे स्थान पर देहरादून है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 235707 रुपए है।
- पर्वतीय ज़िलों में चमोली की सबसे अधिक 127330 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जबकि रुद्रप्रयाग ज़िले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 93160 रुपए वार्षिक है। कुमाऊँ मंडल के बागेश्वर ज़िले की सबसे कम 98,755 रुपए प्रति व्यक्ति आय है।

जिलावार प्रति व्यक्ति आय (रुपए में)

जनपद	2011-12 (आधार वर्ष)	2021-22 (जारी वर्ष)
उत्तरकाशी	49584	1,07281
चमोली	64,327	1,27,330
रुद्रप्रयाग	46,881	93,160
टिहरी	49,854	1,03,345
देहरादून	1,06,552	2,35,707
पौड़ी	50,476	1,08,640
हरिद्वार	1,76,845	3,62,688
पिथौरागढ़	52,413	18,678
बागेश्वर	46,457	98,755
अल्मोड़ा	55,640	1,00844
चंपावत	52,463	1,16,136
नैनीताल	94,142	1,90,627

उत्तराखंड में 'ए-हेल्प' कार्यक्रम की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

13 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, देहरादून में राज्य में 'ए-हेल्प'(पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिये मान्यता प्राप्त एजेंट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा परिकल्पित ए-हेल्प योजना के अंतर्गत महिलाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से संबंधित गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिये चुना गया है।
- 'ए-हेल्प'(A-HELP- Accredited Agent for Health and Extension of Livestock Production) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित ए-हेल्प कार्यकर्त्ता पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे।

- उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु महिला शक्ति का समावेशन और भागीदारी सुनिश्चित करने का एक अतुलनीय उदाहरण होगा।
- उत्तराखंड के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पशुधन क्षेत्र महिलाओं के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है लेकिन अभी तक इसमें संस्थागत समर्थन की कमी थी। इस अंतर को ए-हेल्प कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ पूरा किया जाएगा।
- समुदाय आधारित कार्यकर्त्ताओं का यह नया बैंड, जिन्हें पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिये मान्यता प्राप्त एजेंट (ए-हेल्प) के रूप में नामित किया गया है, स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुधन मालिकों के बीच रिक्तता को भरने और प्राथमिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये तैयार किया गया है।
- आरजीएम के अंतर्गत, पशुधन नस्ल सुधार कार्यक्रम का आयोजन बड़ी संख्या में प्रशिक्षित ए-हेल्प कार्यकर्त्ताओं की सहायता से किया जाएगा, जो अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर कृत्रिम गर्भाधान करवाने में दिल्चस्पी रखते हैं।
- ए-हेल्प कार्यकर्त्ता पशुधन बीमा योजना को लागू करने के साथ-साथ अन्य मध्यवर्तनों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसके लिये उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें कुछ आमदनी और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी), सरकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस नई पहल की शुरुआत की है।
- ए-हेल्प कार्यकर्त्ताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी गाँव में पशुधन आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और पशु सखियों सहित 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने गंगा समग्र 'अविरल गंगा निर्मल गंगा' कार्यक्रम का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों?

16 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन में आयोजित गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रुप में प्रतिभाग कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिये कार्य किये जा रहे हैं जिसमें गंगा को साफ सुथरा रखने के साथ-साथ जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है।
- गंगा के मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिये केंद्र व राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों पर भी कार्य किया जा रहा है।
- प्रथम चरण के तहत गंगा में मिलने वाले 132 गंदे नालों के पानी को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया गया है, जबकि दूसरे चरण के लिये प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

प्रदेश में पाँच ज़िलों में बनेंगे सगंध फसलों के सेटेलाइट केंद्र

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को सगंध पौध केंद्र, सेलाकुई के निदेशक नृपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में सगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिये पाँच ज़िलों में सेटेलाइट केंद्र खोले जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- एरोमा खेती करने वाले किसानों को घर द्वार पर सभी सुविधाएँ देने के लिये सगंध पौध केंद्र सेलाकुई की ओर से पाँच ज़िलों में सेटेलाइट केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है। इससे किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी के साथ ही बीज, पौध सेटेलाइट केंद्र पर भी उपलब्ध होंगे।

- इन केंद्रों के खुलने से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को बीज, पौध के अलावा सगंध खेती की जानकारी लेने के लिये देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- अभी तक किसानों को सगंध खेती का प्रशिक्षण, बीज व पौध के लिये सगंध पौध केंद्र सेलाकुई आना पड़ता है। किसानों को ज़िला स्तर पर सुविधा देने के लिये सेटेलाइट केंद्र बनाए जाएंगे।
- चंपावत ज़िले के खतेड़ा में तेजपात, पिथौरागढ़ के बिसाड़ में तिमूर, उत्तरकाशी के रैथल में सुरई, चमोली के परसारी और अल्मोड़ा ज़िले के ताकुला में डेमस्क गुलाब का सेटेलाइट केंद्र खोला जाएगा।
- विदित है कि राज्य में लगभग आठ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 21 हज़ार किसान सगंध फसलों की खेती कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के सामने जंगली जानवरों, बंदरों और सिंचाई की सुविधा न होना एक बड़ी समस्या है। बाज़ार में सगंध पौध से तैयार होने वाले तेल और इत्र की बाज़ार में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार किसानों को एरोमा खेती के लिये प्रोत्साहित कर रही है।
- गौरतलब है कि 22 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सगंध पौध केंद्र, सेलाकुई में पूरी तरह से सगंध फसलों के लिये समर्पित पहले उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया था।

उत्तराखंड के 603 प्राथमिक, 76 उच्च प्राथमिक बनेंगे क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय ++

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 603 प्राथमिक और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- पाँच किलोमीटर की सीमा में आने वाले इन स्कूलों में सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर आदि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- क्लस्टर उत्कृष्ट स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण किया जाएगा।
- विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इन स्कूलों में खेल सुविधाओं के लिये खेल मैदान विकसित किये जाएंगे।
- क्लस्टर स्कूल को छोड़कर अन्य आस पास के स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिये ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिये छात्र-छात्राओं को तय धनराशि दी जाएगी।
- छात्र-छात्राओं के स्कूल में आने जाने की व्यवस्था तय करने के लिये जनपद स्तर पर संबंधित ज़िले के ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी, जो क्लस्टर स्कूलों में आसपास के स्कूलों से आने वाले छात्र-छात्राओं के एस्कार्ट की सुविधा सुनिश्चित करेगी। जबकि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी छात्र-छात्राओं के लिये ट्रांसपोर्ट की स्थानीय व्यवस्था के लिये कार्ययोजना तैयार करेंगे।

गढ़वाल और कुमाऊँ के छह इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल के छह इंजीनियरिंग कालेज एवं संस्थानों को वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के अधीन कैंपस कालेज के रूप में संचालित किये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट में आए प्रस्ताव के अनुसार तकनीकी संस्थान गोपेश्वर, महिला तकनीकी संस्थान देहरादून, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान टनकपुर, नन्हीं परी सीमांत तकनीकी संस्थान पिथौरागढ़, टीएचडीसी, आईएचईटी नई टिहरी और बौन इंजीनियरिंग कालेज उत्तरकाशी को जैसे हैं, जहाँ हैं के आधार पर कुछ शर्तों के तहत तकनीकी विश्वविद्यालय का कैंपस कॉलेज बनाया जाएगा।

- कैबिनेट बैठक में कहा गया कि कैंपस बनने से सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों में बीओजी पहले की तरह काम करती रहेगी।
- विदित है कि वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की स्थापना 27 जनवरी, 2005 को उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई थी। यह तकनीकी संस्थानों के लिये राज्य का एकमात्र संबद्ध विश्वविद्यालय है।

उत्तराखंड फूड लैब को मिला नया हॉलमार्क

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2023 को राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला आयुक्त आरएस कठायत ने बताया कि भारत सरकार ने रुद्रपुर स्थित खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला को दुग्ध पदार्थों के बाद अब तेल, वसा, मसाले और दालों के लिये भी एनएबीएल (नेशनल एक्रीडिटेशन फॉर बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज) सर्टिफिकेट दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अब रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला से इन खाद्य पदार्थों की जाँच रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगी। मिलावटखोर भी फूड लैब की रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाएंगे।
- रुद्रपुर में वर्ष 2010 में स्थापित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला को वर्ष 2018 में सिर्फ दुग्ध पदार्थों की जाँच रिपोर्ट के लिये एनएबीएल सर्टिफिकेट मिला था। इस कारण दूसरे खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी थम नहीं रही थी। प्रदेश में तेल, मसालों, वसा और दालों में मिलावटखोरी की समस्या अधिक है।
- राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला के प्रभारी निशांत त्यागी ने बताया कि फूड लैब को दुग्ध पदार्थों की जाँच रिपोर्ट में एनएबीएल प्रमाणीकरण के लिये हॉलमार्क मिला था। अब भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने तेल, वसा, मसालों और दालों के लिये भी एनएबीएल सर्टिफिकेट दे दिया है।
- उन्होंने बताया कि खाद्य नमूने फेल होने पर अब तक मिलावटखोर एनएबीएल सर्टिफिकेट न होने का लाभ उठाकर केस दर्ज के बावजूद बच निकलते थे, लेकिन अब मिलावटखोर न्यायालय में फूड लैब की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दे पाएंगे।
- विदित है कि रुद्रपुर स्थित फूड लैब में राज्य के सभी 13 ज़िलों के खाद्य पदार्थों के नमूनों की जाँच होती है। इस लैब की वर्तमान में एक साल में 3000 खाद्य पदार्थों की जाँच की क्षमता है।

गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क माफ

चर्चा में क्यों?

23 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि प्रदेश में रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार ने गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क तीन साल के लिये माफ कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- सचिन कुर्वे ने बताया कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन के तहत रिवर राफ्टिंग की काफी संभावना है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने शुल्क में तीन साल तक छूट दी है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोज़गार उपलब्ध होगा।
- नदियों पर रिवर राफ्टिंग के लिये पर्यटन विभाग की ओर से संचालकों से शुल्क लिया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में 526 से अधिक रिवर राफ्टिंग गाइड पंजीकृत हैं। ऋषिकेश में गंगा में रिवर राफ्टिंग करने के लिये देश व दुनिया से पर्यटक आते हैं। कौड़ियाला से लेकर ऋषिकेश तक राफ्टिंग की जाती है।
- प्रदेश सरकार ने प्रदेश की अन्य नदियों पर रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये शुल्क माफ किया है। इससे बागेश्वर, टनकपुर, रामनगर क्षेत्र में काली, सरयू, रामगंगा, कोसी के अलावा टौंस, यमुना, अलकनंदा नदियों में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तराखंड का माणा अब देश का अंतिम नहीं पहला गाँव

चर्चा में क्यों ?

24 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के चमोली ज़िले में भारत-चीन सीमा पर बसे सीमांत गाँव माणा के प्रवेश द्वार पर सड़क संगठन (बीआरओ) की ओर से देश के अंतिम गाँव के स्थान पर पहले गाँव का साइन बोर्ड लगा दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसकी फोटो राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि अब माणा देश का आखिरी नहीं बल्कि पहला गाँव के रूप में जाना जाएगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गाँव माणा में उसे देश के पहले गाँव के रूप में संबोधित किया था।
- गौरतलब है कि 21 अक्तूबर, 2022 को माणा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा गाँव को भारत के अंतिम गाँव की बजाय देश का पहला गाँव कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सीमाओं पर बसा हर गाँव देश का पहला गाँव कहलाएगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सीमावर्ती क्षेत्र आज वास्तव में और अधिक जीवंत हो रहे हैं। इसके लिये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्य योजनाएँ ज़िला प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायतों के सहयोग से तैयार की गई हैं। इससे इन क्षेत्रों के उत्पादों जड़ी-बूटियों, सेब, राजमा सहित फसलों के साथ-साथ यहाँ विकास की संभावनाओं को पंख लगेंगे।
- यह योजना सीमांत क्षेत्रों से पलायन को रोकने में मददगार होगी और सीमांत क्षेत्रवासी देश की सुरक्षा में भी भागीदारी निभा सकेंगे।
- विदित है कि उत्तराखंड में 3200 मीटर की ऊँचाई पर चमोली ज़िले में स्थित माणा गाँव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ यहाँ से लगभग 5 किमी. दूर है।
- माणा गाँव यहाँ मिलने वाली जड़ी-बूटियों के लिये काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की जड़ी-बूटी खाने से कई तरह की बीमारी में लाभ मिलता है। यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होती है।

WELCOME
BORDER ROADS ORGANISATION
LAST INDIAN VILLAGE
58
सीमान्त ग्राम माणा
MANA

आयुष्मान कार्ड पर अब सेना व पैरामिलिट्री अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज

चर्चा में क्यों ?

- 25 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डी.के कोटिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में संचालित 21 सैनिक और अर्धसैनिक अस्पतालों को आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध कर दिया है, जिसके तहत आयुष्मान कार्डधारकों को अब सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि अभी तक इन अस्पतालों में कार्यरत सैनिकों, उनके आश्रितों और पूर्व सैनिकों को इलाज की सुविधा मिलती है।
- केंद्र सरकार ने इन अस्पतालों को आम लोगों को भी आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिये योजना में शामिल किया है।
- पिथौरागढ़ में 7वीं वाहिनी आईटीबीपी मैरथी, यूनिट अस्पताल 14वीं बटालियन आईटीबीपी, चमोली में यूनिट अस्पताल प्रथम बटालियन आईटीबीपी, यूनिट अस्पताल सीटीसी एसएसबी सापरी, एमआईसी औली, एसएसबी अस्पताल ग्वालदाम, 8वीं बटालियन आईटीबीपी अस्पताल गौचर, नैनीताल में 34वीं बटालियन आईटीबीपी हल्दूचौड़, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ काठगोदाम, 34वीं बटालियन आईटीबीपी यूनिट अस्पताल, ऊधमसिंहनगर ज़िले में ईएसआईसी अस्पताल रुद्रपुर, पौड़ी में यूनिट अस्पताल एसएसबी श्रीनगर, देहरादून में आईटीबीपी अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया है।
- इनके अलावा चंपावत में 5वीं बटालियन एसएसबी, 36वीं बटालियन आईटीबीपी चंपावत, उत्तरकाशी में आईटीबीपी अस्पताल 35 वाहिनी, 12वीं बटालियन आईटीबीपी यूनिट अस्पताल, हरिद्वार में बीएचईएल अस्पताल, ऊधमसिंह नगर में 57वीं बटालियन एसएसबी सितारगंज, देहरादून में आईटीबीपी अकादमिक अस्पताल मसूरी, पिथौरागढ़ में यूनिट अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 50.40 लाख कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए तक मुक्त इलाज की सुविधा है। अब तक 7.36 लाख मरीजों को इलाज की सुविधा मिली है। इसमें 1352 करोड़ की राशि सरकार ने खर्च की है।

जौलीग्रांट में एसडीआरएफ के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 24 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट में एसडीआरएफ के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण किया तथा इस दौरान कई अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ भी कीं।

प्रमुख बिंदु

- एसडीआरएफ का मुख्यालय बनने से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और विभिन्न दुर्घटनाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आएगी। यहाँ अन्य राज्यों की एसडीआरएफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
- एसडीआरएफ के गठन से चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियाँ सुरक्षित हुई हैं। एसडीआरएफ अब तक तीन हज़ार से अधिक रेस्क्यू कर 12 हज़ार घायलों और दो हज़ार शवों को निकाल चुकी है। विभिन्न संस्थाओं के 35 हज़ार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर ढाई लाख लोगों को आपदा राहत कार्यों के लिये जागरूक किया है।
- राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि तीन चरणों में बन रहे एसडीआरएफ मुख्यालय का प्रथम चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण में 36 करोड़ की लागत से ट्रेनिंग सेंटर निर्माणाधीन है।
- विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत जौलीग्रांट में एयरपोर्ट के पास 144 करोड़ रुपए की लागत से एसडीआरएफ का मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है।
- प्रथम चरण में तीन मंज़िला एडमिन ब्लॉक में रिसेप्शन, कार्यालय, प्रशिक्षण ब्लॉक और पुस्तकालय, तीन मंज़िला ट्रेनिंग ब्लॉक, डेमो रूम, कोर्स कॉर्डिनेटर, कंप्यूटर लैब, लेक्चर रूम, लाइब्रेरी की सुविधा है।

- इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन, गैराज और एक दर्जन से अधिक गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है। पुलिस और उनके परिजनों के लिये कैंटीन की सुविधा, फायर फाइटिंग सिस्टम, सोलर सिस्टम, फेंसिंग, वॉच टॉवर और आवासीय कॉलोनी है। पेट्रोल पंप भी है जो आम लोगों के लिये भी उपयोगी होगा।
- मुख्यमंत्री ने कीं ये घोषणाएँ-
  - जोखिम भत्ता : 11 हज़ार फीट या इससे अधिक की ऊँचाई पर रेस्क्यू अभियान चलाने वाले एसडीआरएफ के राजपत्रित अधिकारियों को 1500 रुपए और अराजपत्रित अधिकारियों व जवानों को एक हज़ार रुपए जोखिम भत्ता मिलेगा। यह अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर देय होगा। वर्तमान में केदारनाथ धाम में एसडीआरएफ के 12 अधिकारियों और जवानों की तैनाती है। इसके अलावा समय-समय पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिये जाना पड़ता है।
  - छठी कंपनी : अब एसडीआरएफ में छह कंपनियाँ हो जाएंगी। नई कंपनी का गठन जल्द किया जाएगा। इसमें एक तिहाई महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
  - प्रतिनियुक्ति अवधि : एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति की समयावधि सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी।

आयोग के प्रस्ताव को शासन ने लौटाया, अब उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही होगी PCS परीक्षा

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यूपीएससी पैटर्न लागू करने के प्रस्ताव को ठुकराकर आयोग को वापस भेज दिया। पीसीएस परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा। आगामी पीसीएस परीक्षा पुराने पैटर्न से ही होगी।

प्रमुख बिंदु

- अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को शासनादेश भेज दिया है।
- गौरतलब है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव पास किया था कि चूँकि युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा के लिये अलग और उत्तराखंड पीसीएस के लिये अलग तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए राज्य के युवाओं के हित में पीसीएस परीक्षा में यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न लागू कर दिया जाए।
- इस प्रस्ताव को लेकर प्रदेश भर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आईं थीं। कई लोगों का ये कहना था कि अगर राज्य में भी केंद्र का यूपीएससी पैटर्न लागू कर देंगे तो राज्य के युवाओं के लिये पीसीएस की राह मुश्किल हो जाएगी। यह भी मांग उठी थी कि अगर यूपीएससी पैटर्न लागू करें तो इसमें उत्तराखंड से जुड़े प्रश्नपत्र अलग रखे जाएँ।
- पीसीएस परीक्षा पैटर्न को लेकर आयोग और शासन के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक भी हुई। अब शासन ने तय किया है कि फिलहाल पुराना पैटर्न ही लागू रहेगा। आगामी पीसीएस परीक्षा उसी पैटर्न पर होगी। इसमें किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया गया है।
- इस पुराने पैटर्न पर होगी परीक्षा-
  - पीसीएस प्री परीक्षा: 150 अंकों का सामान्य अध्ययन और 150 अंकों का सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा।
  - पीसीएस मुख्य परीक्षा: सात पेपर होते हैं। पहला- भाषा (300 अंकों का), दूसरा- भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति (200 अंकों का), तीसरा- भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (200 अंकों का), चौथा- भारत एवं विश्व भूगोल (200 अंकों का), पाँचवा- आर्थिक एवं सामाजिक विकास (200 अंकों का), छठा- सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (200 अंकों का) और सातवाँ- सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र (200 अंकों का)। पीसीएस परीक्षा में भाषा के पेपर में कम-से-कम 35 अंक लाने जरूरी हैं।
  - इंटरव्यू: 200 अंकों का।

उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन

चर्चा में क्यों?

26 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। उन्होंने बागेश्वर के एक अस्पताल में अंतिम साँस ली।

प्रमुख बिंदु

- परिवहन मंत्री चंदन रामदास बागेश्वर धाम गए हुए थे, जहाँ उनकी तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बागेश्वर के ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका निधन हो गया।
- उत्तराखंड की अब तक की सरकारों में वह तीसरे कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके निधन की वजह कोई न कोई बीमारी बनी है। उनसे पहले कुमाऊँ के दिग्गज राजनेता प्रकाश पंत और हरिद्वार ज़िले के नेता सुरेंद्र राकेश की मृत्यु कैंसर से हुई थी। सुरेंद्र राकेश कॉन्ग्रेस सरकार में मंत्री थे, जबकि प्रकाश पंत भाजपा सरकार में मंत्री थे।
- प्रदेश के परिवहन कल्याण मंत्री बागेश्वर के विधायक चंदन रामदास का राजनीतिक करियर 1980 में शुरू हुआ। वह 1997 में नगरपालिका बागेश्वर के निर्दलीय अध्यक्ष बने। इससे पूर्व एम.बी. डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में बी.ए. प्रथम वर्ष में निर्विरोध संयुक्त सचिव बने।
- 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की प्रेरणा पर चंदन रामदास भाजपा में शामिल हुए थे। 2007, 2012, 2017 और 2022 में वह लगातार चौथी बार विधायक चुने गए। उनके निधन पर 26 से 28 अप्रैल तक प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया है।

एयर एंबुलेंस सेवा के लिये एम्स और पिनाकल कंपनी में हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों?

27 अप्रैल, 2023 को एम्स ऋषिकेश और पिनाकल कंपनी के बीच एयर एंबुलेंस संचालित करने के लिये एमओयू किया गया। आपातकालीन और ट्रामा सेवाओं के लिये मई में एम्स से एयर एंबुलेंस सेवा संचालित होगी।

प्रमुख बिंदु

- आपातकालीन व ट्रामा सेवा के लिये गंभीर मरीज़ों को तत्काल एम्स पहुँचाने के लिये केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पहली बार एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की जाएगी।
- एम्स ऋषिकेश की निदेशक डॉ. मीनू सिंह ने बताया कि एयर एंबुलेंस के लिये पिनाकल कंपनी की ओर से सेवा दी जाएगी, जबकि पवन हंस एयर एंबुलेंस के लिये हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएगा। हेलीकॉप्टर उपलब्ध होते ही सेवा शुरू की जाएगी।
- एयर एंबुलेंस सेवा के लिये एक महीने में 50 ट्रिप निर्धारित किये गए हैं। आपात और ट्रामा सेवा के लिये किसी मरीज को तत्काल एयर एंबुलेंस की जरूरत है या नहीं यह एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों की टीम तय करेगी। टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीज की स्थिति को देखा जाएगा।

The Vision

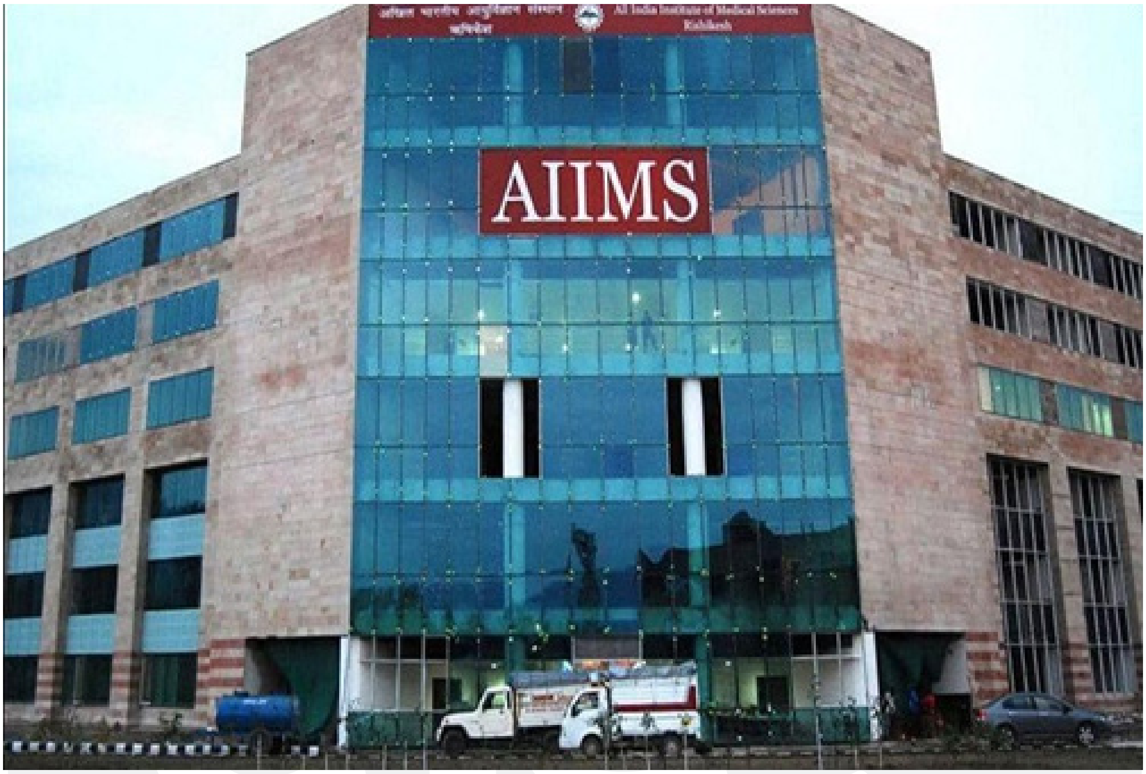
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ऋषिकेश
All India Institute of Medical Sciences
Rishikesh
AIIMS

एम्स ऋषिकेश

The Vision